

जे0 पी0 जोशी संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग- 1

देहरादूनः दिनांकः / 🗲 मई, 2013

विषयः 31 वीं वाहिनी पी० ए० सी० रुद्रपुर, जनपद—उधमसिंहनगर में टाइप द्वितीय के 42 आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-डीजी-दो-146(1)/2006, दिनांक 04.12.2012 के कम में व शासनादेश संख्या-32/ XX(1)/37-निर्माण/आयोजनागत/2007-2008, दिनांक: 08-01-2008 एवं 902/XX-1-2013-4(58)2007, दिनॉक: 25 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय 31 वीं वाहिनी पीं0 ए० सीं0 रुद्रपुर, जनपद-उधमसिंहनगर में टाइप दितीय के 42 आवासीय भवनों के निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नकानुसार अवशेष रु021,85,000.00(रुपये इक्कीस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी। कार्य की प्रगति में तेजी लाने तथा कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण

किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को अवश्य निर्देशित किया जाय।

3- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4— प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। किसी भी दशा में विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायगा।

- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन

तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

8— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय शीघ्र सुनिश्चित कर इसका वित्तीय/भौतिक

प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें।

10— निर्माण एजेंसी के साथ वित्त विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रयत्र पर एम०ओ०यू० कर िाया

11— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय—व्ययक वर्ष 2013—14 के अनुदान सं0—10 लेखाशीर्षक 4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, 211—पुलिस आवासं —00—आयोजनागत, 03 पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य)-00- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०— ०५ (P) / वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—५ / २०१३ दिनांकः ०९.०५.२०१३ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकःयथोक्त् ।

भवदीय, (जे0 पी जोशी) संयुक्त सचिव,

संख्या—1206 (1)/xx-1—2013—4(58)2007, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:— 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।

महालखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून
निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

4- जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।

5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर।

6- सेनानायक, 31 वीं वाहिनी पी० ए० सी०,रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।

वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।

9- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।

10- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-5 / नियोजन विभाग / एन०आई०सी०।

12- गार्ड फाईल।

संलग्नक्:यथोक्त।

आज्ञा से (विक्रम सिंह यादव) अनु सचिव

शासनादेश सं0-1206 /xx-1-2013-4(58)2007, दिनाँकः / रेमई, 2013 का संलग्नक

1			(धनराशि रू० लाख में)			
क्र. सं	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	अबतक अवमुक्त धनराशि	2013-14 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	31 वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 रुद्रपुर में 42 आवासीय भवनों का निर्माण।	उधमसिंहनगर	सिंचाई विभाग	176.08	154.23	21.85
योग-				176.08	154.23	21.85

(रूपये इक्कीस लाख पचासी हजार मात्र)

(जेo पीo जोशी) संयुक्त सचिव